International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राष्ट्रों की समृद्धि और गरीबी में सूक्ष्म वित्त का प्रभाव: भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक निबंध

Dr Hemant Kumar[1], Dr Priyamwada Kumari[2]

[1]Assistant Professor, Department of Economics, Patna Women's College (Autonomous), Patna University, Patna
[2]Department of Economics, Patna Women's College (Autonomous), Patna University, Patna

सारांश
सूक्ष्म वित्त उन छोटे विचारों में से एक है, जो बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। जब बांग्लादेश विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने 1970 के दशक में स्थानीय ग्रामीणों को छोटे ऋण देना शुरू किया, तो यह स्पष्ट नहीं था कि यह विचार कहाँ तक जाएगा। दुनिया भर में, कई सरकारी बैंकों ने पहले ही गरीब परिवारों को ऋण देने की कोशिश की थी, और उन्होंने अकुशलता, भ्रष्टाचार और लाखों डॉलर की बर्बाद सब्सिडी की विरासत छोड़ी।आर्थिक सिद्धांत ने उन निम्न आय वाले परिवारों को ऋण देने के प्रति भी पर्याप्त सावधानी बरती है, जिनके पास ऋण सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक नहीं होता। सूक्ष्म वित्त की सफलताएं अर्थशास्त्रियों को इस बारे में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती हैं कि गरीब परिवार किस तरह से बचत और संपत्ति बनाते हैं तथा संस्थाएं बाजार की विफलताओं पर कैसे काबू पा सकती हैं। सूक्ष्म वित्त सामाजिक-आर्थिक और समृद्धि परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है

मुख्य शब्द: सूक्ष्म वित्त, माइक्रोक्रेडिट गरीबी, आर्थिक, स्वयं सहायता समूह

परिचय:
सूक्ष्म वित्त बाज़ारों का विस्तार करने, गरीबी कम करने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कई संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। लेकिन यह कई पहेलियाँ भी प्रस्तुत करता है जिनमें से कई पर अभी तक व्यापक रूप से चर्चा नहीं हुई है। सूक्ष्म वित्त अनुभव से प्राप्त कई अंतर्दृष्टि को अर्थशास्त्र में हाल के नवाचारों (विशेष रूप से सूचना का अर्थशास्त्र, अनुबंध सिद्धांत और तंत्र डिजाइन दृष्टिकोण) के लेंस के माध्यम से फलदायी रूप से देखा जा सकता है। अन्य सूक्ष्म वित्त अंतर्दृष्टि उन क्षेत्रों की ओर इशारा करती हैं जहाँ नए शोध की आवश्यकता है, विशेष रूप से गरीबों द्वारा बचत करने की संभावनाओं और बाधाओं के बारे में और सामाजिक प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए। यूनुस (1994) के अनुसार, एक सद्गुण चक्र स्थापित किया जा सकता है जैसे "कम आय, ऋण, निवेश, अधिक आय, अधिक ऋण, अधिक निवेश और अधिक आय"
ग्रामीण मॉडल बैंक: इस मॉडल को विक 1970 क दशक म एक बाग्लादशी नोबल ववजता प्रोफेसर महम्मद युनुस ने किया । इस मॉडल ने भारत मे क्षत्रीय ग्रामीण बकों के निर्माण को प्रेरित किया और इस प्रणाली का प्रथामिक उद्देश्य ग्रामीण अथकव्यवस्था का विकास करना है।
सूक्ष्म वित्त की सफलता आंशिक रूप से अतीत की गलतियों से सावधानीपूर्वक बचने पर निर्भर करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब निम्न आय वाले देशों ने अपने कृषि क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास किया, तो ग्रामीण वित्त भी एक

बड़ी चिंता के रूप में उभरा। बड़े राज्य कृषि बैंकों को धन आवंटित करने की जिम्मेदारी दी गई, इस उम्मीद के साथ कि सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने से किसान सिंचाई करने, उर्वरक लगाने और नई फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे (,भारतीय रिजर्व बैंक 1954)।

दुनिया भर के उद्यमी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विकास विशेषज्ञ माइक्रोबैंक और गैर सरकारी संगठनों की ओर आकर्षित हुए हैं। वे सूक्ष्म वित्त के माध्यम से खुदरा बैंकिंग के बारे में सबक से आकर्षित होते हैं सूक्ष्म वित्त के प्रमुख सफलता पहलू उचित विपणन तकनीक, प्रमुख परिचालन सिद्धांत, गरीबी उन्मूलन में सूक्ष्म वित्त की भूमिका और आर्थिक विकास का प्रबंधन हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई थी, और उस घोषणा के अनुच्छेद 25 (1) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और भलाई के लिए 7 मानक जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास और चिकित्सा देखभाल, और आवश्यक सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं, और बेरोजगारी, बीमारी विकलांगता, विधवापन, बुढ़ापे या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों में आजीविका की कमी के मामले में सुरक्षा का अधिकार है।

सिद्धांत:

प्रारंभिक अर्थशास्त्र पूंजी पर घटते सीमांत प्रतिफल का सिद्धांत है, जो कहता है कि अपेक्षाकृत कम पूंजी वाले उद्यमों को अपने निवेश पर अधिक पूंजी वाले उद्यमों की तुलना में अधिक प्रतिफल अर्जित करने में सक्षम होना चाहिए।

"घटते प्रतिफल का सिद्धांत" उत्पादन कार्यों की कल्पित अवतलता से लिया गया है, अवतलता बहुत ही प्रशंसनीय धारणा का उत्पाद है कि जब कोई उद्यम अधिक निवेश करता है (यानी, अधिक पूंजी का उपयोग करता है), तो उसे अधिक उत्पादन की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन पूंजी की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई छोटे और छोटे वृद्धिशील ("सीमांत") लाभ लाएगी। जब एक दर्जी अपनी पहली 1000 की सिलाई मशीन खरीदता है, तो उत्पादन उत्पादन के सापेक्ष तेज़ी से बढ़ सकता है

अवतल उत्पादन फ़ंक्शन के साथ पूंजी पर सीमांत रिटर्न और गरीब उद्यमी को अपनी पूंजी की अगली इकाई पर अधिक रिटर्न मिलता है और वह अमीर उद्यमी की तुलना में अधिक ब्याज दर का भुगतान करने को तैयार होता है।

ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त क्रांति और माइक्रोक्रेडिट

सूक्ष्म वित्त की जड़ें कई जगहों पर पाई जा सकती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी मुहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। 1970 के दशक के मध्य में, बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा था।

"माइक्रोक्रेडिट" - जो विशेष रूप से छोटे ऋणों को संदर्भित करता है और "सूक्ष्म वित्त " में बदलाव। व्यापक शब्द में कम आय वाले परिवारों से बचत एकत्र करने, बीमा ("माइक्रोइंश्योरेंस") प्रदान करने और, कुछ स्थानों पर (बांग्लादेश में BRAC ने यहां अग्रणी भूमिका निभाई है) ग्राहकों के उत्पादन को वितरित करने और विपणन करने में भी मदद करने के प्रयास शामिल हैं। रॉबिन्सन (2001) "सूक्ष्म वित्त क्रांति" का एक समृद्ध विवरण प्रदान करता है जो अभी शुरू हो रही है।

जबकि माइक्रोक्रेडिट और सूक्ष्म वित्त शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनके अलग-अलग अर्थ हैं और वे ग्रामीण वित्त की स्थिति और गरीबी की प्रकृति के बारे में विपरीत मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। माइक्रोक्रेडिट शब्द का इस्तेमाल शुरू में ग्रामीण बैंक जैसी संस्थाओं के लिए किया गया था, जो बहुत गरीब लोगों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। इसका ध्यान स्पष्ट रूप से गरीबी कम करने और सामाजिक बदलाव पर था, और इसमें मुख्य भूमिका एनजीओ की थी।

"सूक्ष्म वित्त" को बढ़ावा इस मान्यता के साथ मिला कि परिवारों को अधिक व्यापक रूप से परिभाषित वित्तीय सेवाओं तक पहुँच से लाभ हो सकता है (पहले मुख्य रूप से बचत पर ध्यान केंद्रित किया जाता था) और न केवल सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण, "कम गरीब" परिवारों की ओर तथा वाणिज्यिक रूप से उन्मुख, पूर्णतः विनियमित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की ओर और बचत को अपनाने का प्रयास स्वागत योग्य है, क्योंकि यह बचत के लिए सुरक्षित स्थानों की बढ़ती मांग को पहचानता है

भारत में सूक्ष्म वित्त:

भारत में सूक्ष्म वित्त की जड़ें 1970 के दशक में देखी जा सकती हैं, जब वंचित ग्रामीण आबादी को ऋण प्रदान करने के लिए छोटे-छोटे प्रयोग किए गए थे। हालाँकि, 1990 के दशक में सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) ने गति पकड़ी। अग्रणी संस्थाओं में से एक, स्व-रोजगार महिला संघ (सेवा) ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए सूक्ष्म वित्त की क्षमता का प्रदर्शन किया।

भारत का एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) कई लोगों के लिए अकुशल सब्सिडी वाले ऋण का एक आदर्श उदाहरण है। इस कार्यक्रम ने "सामाजिक लक्ष्यों" के अनुसार ऋण आवंटित किया, जिसने सिद्धांत रूप में 30 प्रतिशत ऋण सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों (जैसा कि "अनुसूचित" जनजाति या जाति का सदस्य होने से संकेत मिलता है) और 30 प्रतिशत महिलाओं को दिया। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना दक्षता प्राप्त करने जितना ही महत्वपूर्ण हो गया। इस प्रणाली के तहत, पूंजी को नेस्टेड नियोजन अभ्यासों की एक श्रृंखला के अनुसार आवंटित किया गया था, जिसमें ग्राम योजनाओं को ब्लॉक योजनाओं में एकत्रित किया गया था, जो जिला योजनाओं में एकत्रित होकर राज्य योजनाओं में एकत्रित हो गईं। 1979 और 1989 के बीच, जो कि तीव्र आईआरडीपी वृद्धि की अवधि थी, सब्सिडी $6 बिलियन (कमजोर क्षेत्रों को दिए गए ऋण की मात्रा का लगभग 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत) थी। उन संसाधनों ने अच्छा संस्थागत प्रदर्शन नहीं किया।

सूक्ष्म वित्त के स्रोत

सूक्ष्म वित्त सेवाएँ विविध स्रोतों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जो वंचित समुदायों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इन स्रोतों में शामिल हैं:

1. **औपचारिक संस्थाएं:** इनमें ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां शामिल हैं, जो सूक्ष्म वित्त वितरण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।
2. **अर्ध-औपचारिक संगठन:** गैर-सरकारी संस्थाएं सूक्ष्म वित्त में योगदान देती हैं, तथा एक संकर मॉडल उपलब्ध कराती हैं जो औपचारिक और अनौपचारिक दृष्टिकोणों के बीच सेतु का काम करता है।
3. **अनौपचारिक स्रोत:** लघु-स्तरीय ऋणदाता और स्थानीय स्टोर मालिक भी सूक्ष्म वित्त में भूमिका निभाते हैं, तथा स्थानीयकृत और सुलभ वित्तीय समाधान प्रदान करते हैं।

भारत में सूक्ष्म वित्त परिदृश्य में वाणिज्यिक बैंक, NBFC, MFI, फिनटेक, NGO, सरकारी बैंक क्षेत्र और सहकारी संस्थाओं सहित विभिन्न श्रेणियों के संस्थान शामिल हैं। ये संस्थाएँ सूक्ष्म वित्त संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को तालमेलपूर्वक पूरक बनाती हैं। माइक्रोक्रेडिट के अलावा, वे बीमा, बचत और प्रेषण जैसी कई वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं

सूक्ष्म वित्त का प्रभाव

सूक्ष्म वित्त को एक छत के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय सेवाएँ शामिल हैं, जिसमें माइक्रो-क्रेडिट शामिल है जो निम्न-आय वर्ग को प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म वित्त के विकास की आवश्यकता विकासशील देशों में चालीस साल से भी पहले शुरू हुई थी। सूक्ष्म वित्त का तात्पर्य ऋण और जमा दोनों के लिए छोटे पैमाने की वित्तीय सेवाओं से है जो उन लोगों के लिए हैं, जो खेती करते हैं, छोटे या सूक्ष्म उद्यम करते हैं जिनमें माल का उत्पादन, पुनर्चक्रण, मरम्मत या व्यापार किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबों को आत्मनिर्भरता से जीने के साधन खोजना था। जिनके पास आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए कोई साधन या रोजगार के अवसर नहीं थे.

सूक्ष्म वित्त गरीब लोगों, खासकर महिलाओं और हाशिए पर पड़े वर्गों के औपचारिक वित्तीय तकनीकों से संस्थागत बहिष्कार से निपटने की रणनीति के रूप में उभरा है। सूक्ष्म वित्त हाशिए पर पड़े लोगों की गरीबी और भेद्यता को कम करने के लिए उन्नत आर्थिक गतिविधि कर रहा है, इसलिए पर्याप्त ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राहक की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राहक उद्यमिता को बढ़ाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना सूक्ष्म वित्त संस्थानों की अपरिहार्य गतिविधियाँ हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों का कार्य उपभोक्ता आय बढ़ाने और हाशिए पर पड़े ग्राहकों के लिए आर्थिक संतुलन को विनियमित करने में सहायता करना है। सूक्ष्म वित्त की अभिनव वित्तीय सेवाएँ जैसे ऋण और बचत ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में मदद करती हैं।

सशक्तिकरण और उन्मूलन

चुनौतियों के बावजूद, भारत में सूक्ष्म वित्त का प्रभाव उल्लेखनीय रहा है:

1. **गरीबी उन्मूलन:** सूक्ष्म वित्त ने गरीबों को आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण तक पहुंच प्रदान की है, जिससे गरीबी का चक्र टूट गया है और आर्थिक गतिशीलता सक्षम हुई है।
2. **महिला सशक्तिकरण:** सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं में एक महत्वपूर्ण अनुपात महिलाओं का है। ऋण तक पहुँच ने उन्हें अपने घरों और समुदायों में सक्रिय भागीदार बनने के लिए सशक्त बनाया है।
3. **वित्तीय समावेशन:** सूक्ष्म वित्त ने बैंकिंग सुविधा से वंचित और अल्प बैंकिंग सुविधा वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।
4. **रोजगार सृजन:** सूक्ष्म वित्त से प्राप्त धन ने छोटे व्यवसायों के विकास में योगदान दिया है, जिससे रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
5. **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल:** ऋण तक बेहतर पहुंच ने परिवारों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र कल्याण में सुधार हुआ है।
6. **सामुदायिक विकास:** स्वयं सहायता समूहों और समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से, सूक्ष्म वित्त ने सामाजिक सामंजस्य और सामुदायिक विकास को सुगम बनाया है।

स्वयं सहायता समूह बैंक से जुड़ा हुआ कार्यक्रम की प्रगति

बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूह के प्रसार ने वित्त वर्ष 1992 में 255 स्वयं सहायता समूह के गठन से लेकर वित्त वर्ष 2024 में 144.22 लाख स्वयं सहायता समूह तक का उल्लेखनीय विस्तार प्रदर्शित किया है। साथ ही, स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण 1992 में ₹29 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक ₹2,09,286 करोड़ हो गया। हालांकि, बचत से जुड़े स्वयं सहायता समूह की साल-दर-साल वृद्धि 2022-2023 के दौरान 12.7% से घटकर 2023-24 में 7.6% हो गई। यह कमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में स्वयं सहायता समूह गठन में संतृप्ति के कारण हो सकती है, जो सभी क्षेत्रों में सबसे कम ऋण अंतर (24.23%) में परिलक्षित होती है।

बैंकिंग क्षेत्र के साथ स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम 2023-24 के तहत समग्र प्रगति:

S.N	विशिष्ट	कुल	
		Physical in Lakh	Financial in Crore
1.	31 मार्च 2024 तक बैंकों से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की बचत की कुल संख्या	144.22	65089.15
	कुल SHG में से - विशेष महिला SHG	120.44	55227.69
	कुल SHG से एनआरएलएम/एसजीएसवाई के तहत	84.30	45384.39
	SHGs -under NULM/SJSRY	7.40	4354.31
2.	वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ऋण-लिंक्ड SHGs	54.82	209285.87
	SHGs - विशेष महिला SHG	53.20	202716.08
	SHGs – under NRLM/SGSY	44.89	169797.41
	SHGs – under NULM/SJSRY	2.70	13499.66
3.	31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण वाले स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या	77.42	259663.73
	SHGs - विशेष महिला SHG	72.30	246895.32
	SHGs - under NRLM/SGSY	61.02	207138.48
	SHGs - under NULM/SJSRY	3.94	15313.61

स्रोत: नाबार्ड

भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र विकास और चुनौतियों दोनों का अनुभव कर रहा है। 30 सितंबर, 2024 तक, बकाया पोर्टफोलियो 1,265 लाख सक्रिय ऋणों और 7.7 करोड़ अद्वितीय जीवित उधारकर्ताओं के साथ ₹3,73,918 करोड़ था। हालाँकि, चूकें और भी बदतर हो गई हैं, 90-दिन से अधिक की चूकें 2.30% तक पहुँच गई हैं। जबकि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें बकाया पोर्टफोलियो में 18% वार्षिक वृद्धि शामिल है, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से कम लागत वाले, दीर्घकालिक फंड की आवश्यकता और कम उधार के प्रभाव के संबंध में।

मुख्य विशेषताएं:

- पोर्टफोलियो बकाया: ₹3,73,918 करोड़ (30 सितंबर, 2024 तक)।
- सक्रिय ऋण: 1,265 लाख।
- अद्वितीय जीवित उधारकर्ता: 7.7 करोड़।
- पोर्टफोलियो बकाया में वार्षिक वृद्धि: 18%
- 90-दिन से अधिक की चूक: 2.30% (30 सितंबर, 2024 तक)
- एनबीएफसी-एमएफआई: पोर्टफोलियो बकाया में सबसे अधिक योगदान करते हैं।
- आकांक्षी जिले: आकांक्षी जिलों में पोर्टफोलियो बकाया ₹53,483 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक) था, जिसमें 23% की वृद्धि हुई।

- चुनौतियाँ: कम लागत वाले, दीर्घकालिक फंड जुटाने में कठिनाइयाँ और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कम उधार

विकास और रुझान:

- सूक्ष्म वित्त उद्योग ने मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 में पोर्टफोलियो बकाया में 18% वार्षिक वृद्धि का अनुभव किया।
- एनबीएफसी ने पोर्टफोलियो बकाया में 45% की उच्चतम वृद्धि देखी।
- सूक्ष्म वित्त उद्योग ने दिसंबर 2023 की तुलना में मार्च 2024 में पोर्टफोलियो बकाया में 4% तिमाही वृद्धि और मूल्य के हिसाब से संवितरण में 8% की वृद्धि देखी।
- एसएफबी ने ओएनडी'23 से जेएफएम'24 तक ऋण वितरण में 17% की उच्चतम वृद्धि देखी।

निष्कर्ष और सारांश

भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) उद्योग ने पिछले 12 वर्षों में 2,176 प्रतिशत से अधिक की तीव्र वृद्धि देखी है, जिसका कारोबार मार्च 2012 में 17,264 करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर 2024 तक 3.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है सूक्ष्म वित्त ने वित्त वर्ष 2023 में 21% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष के 2,89,845 करोड़ रुपये की तुलना में 3,51,521 करोड़ रुपये थी। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि एनबीएफसी और एमएफआई ने इसी अवधि में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है (क्रमशः 49% और 37%)। वित्त वर्ष 2021-22 में 2,53,966 करोड़ रुपये की तुलना में सभी ऋणदाताओं का कुल संवितरण 3,19,948 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म वित्त के लिए ऋण खातों की संख्या में वित्त वर्ष 2022-23 में 10% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

सूक्ष्म वित्त इन समस्याओं के समाधान के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। यह गरीब परिवारों के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देता है कि वे क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं, और अधिक व्यापक रूप से, कम आय वाले समुदायों में स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अभिनव अनुबंधों और संस्थानों की क्षमता को दर्शाता है। सूक्ष्म वित्त 1960 के दशक में उभरे विकास बैंकों की तुलना में एक स्पष्ट सुधार है, लेकिन कम समय में पूर्ण वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल करने का निहित "वादा" पूरा होने से बहुत दूर है। नाबार्ड ने "सूक्ष्म वित्त को ग्रामीण, अर्ध-शहरी या शहरी क्षेत्रों में मूल रूप से गरीब लोगों के लिए बहुत छोटी राशि के बचत, ऋण और कई अन्य प्रकार की वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया है और यह प्रावधान इन लोगों को उनकी आय के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए है" क्या केवल वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके गरीबी को सबसे प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है? या क्या "पूरक" सेवाओं का एकीकृत प्रावधान उचित लागत पर महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है? सूक्ष्म वित्त सबसे तेज़ी से कम आय वाले देशों में बढ़ा है, लेकिन अमीर देशों में कई गरीब परिवारों को उचित कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय सेवाओं तक पहुँच की कमी है।

सूक्ष्म वित्त सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर कम आय वाले और वंचित समुदायों में। पारंपरिक रूप से औपचारिक वित्तीय संस्थानों से बाहर रखे गए व्यक्तियों को ऋण, बचत, बीमा और भुगतान प्रणाली जैसी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके, सूक्ष्म वित्त व्यक्तियों को गरीबी के चक्र से मुक्त होने का अधिकार देता है। यह अधिकार विभिन्न रूपों में मिलता है, जिसमें उद्यमिता और आजीविका सृजन को बढ़ावा देना, महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच को सक्षम बनाना शामिल है।

भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक वित्तीय समावेशन की दिशा में सूक्ष्म वित्त एक अपरिहार्य साधन के रूप में उभर रहा है। आर्थिक रूप से वंचित लोगों को ऋण देने के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण देश के भीतर परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित कर सकता है, जो एक चमत्कारी विकास के समान है।

संदर्भ:

1. Adams, Dale W. 1984. "Are the arguments for cheap agricultural credit sound?" In Dale W. Adams, Douglas H. Graham, and J. D. von Pischke, eds., Undermining Rural Develop ment with Cheap Credit. Boulder, CO: Westview Press.
2. Ahlin, Christian, and Robert Townsend. 2003b. "Selection into and across credit contracts: Theory and field research." Working Paper No. 03-W23, Department of Economics, Vanderbilt University, October.
3. Aleem, Irfan. 1990. "Imperfect information, screening, and the costs of informal lending: Astudy of a rural credit market in Pakistan." World Bank Economic Review 4(3): 329–349.
4. Armendáriz de Aghion, Beatriz. 1999b. "Development banking." Journal of Development Economics 58 (February): 83–100.
5. Bayulgen, O. (2008). Muhammad Yunus, Grameen Bank and the Nobel Peace Prize: What political science can contribute to and learn from the study of microcredit. International Studies Review, 10(3), 525-547.
6. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/0808244223NABARD-SOMFI%20%20%20%20%20%20%20%2020232024%20%20%20%20%20%2030072024.pdf
7. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/status-of-microfinance-in-india-2022-23.pdf
8. Reserve Bank of India (RBI) 1954. All-India Credit Survey. Bombay: RBI.
9. Robinson, M. (2001). The microfinance revolution: Sustainable finance for the poor. World Bank Publications.
10. Robinson, M. (2001). The microfinance revolution: Sustainable finance for the poor. World Bank Publications.